



सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या—cm-261
12/06/2017

मुख्यमंत्री के लोक संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन

पटना, 12 जून 2017 :- मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभाकक्ष में आज लोक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन, पुलिस, गृह, निगरानी, पंचायती राज, सहकारिता, नगर विकास एवं आवास, मद्य निषेध निबंधन एवं उत्पाद विभाग, वाणिज्य कर, राजस्व एवं भूमि सुधार, खान एवं भू-तत्व, परिवहन तथा आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित मामलों पर 05 लोगों द्वारा मुख्यमंत्री को अपना सुझाव दिया गया।

आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम में पटना के श्री सुबोध कुमार, पटना के श्री अमित सिंह, पटना की श्रीमती सीमा सिंह, भागलपुर के श्री राजीव झा और औरंगाबाद के श्री दिनेश प्रसाद सिंह ने अपने-अपने सुझाव एवं राय मुख्यमंत्री को दिये। प्राप्त सुझाव एवं राय पर संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव ने वस्तुस्थिति को स्पष्ट किया। लोगों से प्राप्त सुझाव एवं राय पर मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया।

आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री श्री आलोक कुमार मेहता, नगर विकास एवं आवास मंत्री श्री महेश्वर हजारी, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ० मदन मोहन झा, परिवहन मंत्री श्री चन्द्रिका राय, खान एवं भूतत्व मंत्री श्री मुनेश्वर चौधरी, आपदा प्रबंधन मंत्री श्री चन्द्र शेखर, पंचायती राज मंत्री श्री कपिलदेव कामत, मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री पी०के० ठाकुर, प्रधान सचिव मंत्रिमण्डल समन्वय श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा सहित संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव उपस्थित थे।

आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम के पश्चात् मुख्यमंत्री ने मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा किसानों के आंदोलन से संबंधित पूछे गये प्रश्न पर कहा कि आज एग्रेरियन क्राइसिस (कृषि संकट) की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि फसलों की उत्पादकता बढ़ी है, परंतु किसानों को उसका सही दाम नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अकेले कर्ज माफी इस समस्या का समाधान नहीं है। अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग समस्या है। उन्होंने कहा कि कृषि संकट का मुख्य कारण यह है कि किसानों की फसल उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है, परंतु किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, मूल समस्या यही है। उन्होंने कहा कि 2014 लोकसभा के पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किये गये वादा जो भाजपा के घोषणा पत्र में भी था, कि किसानों को उनके लागत मूल्य के ऊपर 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जायेगा को पूरा करना चाहिये। उन्होंने कहा कि मैं इस प्रश्न को निरंतर उठाते रहा हूँ, यही आज की समस्या का निदान है। बी०टी० कॉटन का उदाहरण देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को ऐसा लगा था कि इससे बीमारियों से मुक्ति मिल जायेगी, परंतु बी०टी० कॉटन आने से मल्टीनेशनल कंपनियों ने बीजों पर मोनोपॉली कर ली। उन्होंने कहा कि उसी तरह जी०एम० सीड का हाल है, हम शुरू से इसका विरोध कर रहे हैं। पर्यावरणविद् तथा कृषि विशेषज्ञों ने भी इसका

विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जी०एम० सीड के प्रभाव का अध्ययन होना चाहिये। जी०एम० सीड पर मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी मोनोपॉली बनायेगी, मुनाफा कमायेंगी तथा किसान उन पर निर्भर हो जायेंगे। उन्होंने कहा कि सरसों के जी०एम० सीड का सीधा प्रभाव मधु उत्पादन पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इन सभी चीजों से किसान के उत्पादन मूल्य की वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि आज स्वीयल हेल्थ कार्ड की बात की जा रही है, परंतु मिट्टी की समस्याओं को दूर करने का भी इंतजाम होना चाहिये। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में बेहतर नीति बनानी होगी। फसल बीमा योजना का उदाहरण देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से फसल बीमा कंपनियों को फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा कंपनियों के द्वारा कितने किसानों को फसल बीमा योजना अंतर्गत भुगतान किया गया है ? मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बिहार में कृषि रोड मैप बनाया है। हमारा मुख्य उद्देश्य है किसानों की आमदनी बढ़े। सीमित दायरे में जो कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को पहल करनी पड़ेगी। किसी मंत्रालय का सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं होगा। किसानों को दी जा रही समर्थन मूल्य में वृद्धि होनी चाहिये। किसानों की आमदनी बढ़े, उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए राष्ट्र स्तर पर नीतियाँ बननी चाहिये।

बिहार में पुनः मतदान कराने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बिहार में चुनाव के लिये तैयार हैं, परन्तु साथ ही साथ भाजपा यू०पी० में भी चुनाव कराये। यू०पी० और बिहार के लोकसभा सदस्य इस्तीफा दें और पुनः मतदान कराया जाये। हमें चुनौती स्वीकार है। गाँधीजी के संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह द्वारा दिये गये बयान पर पूछे गये प्रश्न के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि गाँधी जी तो स्थिर हैं, इससे लोगों की मानसिकता सामने आती है। उन्होंने कहा कि बिहार में गाँधी जी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर हम पूरे साल गाँधी जी के विचारधारा को जन-जन तक पहुँचायेंगे। हमारा दृढ़ भावना है कि अगर 10 से 15 प्रतिशत लोगों ने भी गाँधी जी के विचारों को अपना लिया तो समाज बदल जायेगा। उन्होंने कहा कि आज चारों तरफ जो असहिष्णुता का माहौल है, इससे मुक्ति पाने के लिए गाँधी जी के विचारों को अपनाना ही एक रास्ता है। इसी से देश आगे बढ़ेगा। सेनाध्यक्ष पर काँग्रेस नेता श्री संदीप दीक्षित के बयान पर पूछे गये प्रश्न के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि सेनाध्यक्ष को अपनी जिम्मेवारी निभाने में पूरे देश का समर्थन है, भारतीय सेना के प्रति पूरे देश में सम्मान का भाव है। राष्ट्रपति चुनाव के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता पक्ष की तरफ से आम सहमति बनाने की पहल होनी चाहिये। ऐसा नहीं होने पर विपक्ष के उम्मीदवार की बात होगी।
